

प्रेषक,

डी०एस० गब्याल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

ऊधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 06 जुलाई, 2016

विषय:- जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत खुरपिया फार्म की सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि में से 1002.15 एकड़ भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1536/पांच-सीलिंग/2015 दिनांक 09.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत खुरपिया फार्म की सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि में से 1002.15 एकड़ भूमि विभिन्न खसरा नम्बरों में अलग-अलग सर्किल रेट के अनुसार कुल आंकलित धनराशि रु.1,58,33,93,400 (एक अरब अठ्ठावन करोड़ तैंतीस लाख तिरानबे हजार चार सौ मात्र) के अनुसार एकीकृत औद्योगिक आस्थान (Integrated Intustrial Estate) (IIE) स्थापित किये जाने हेतु राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि०(सिडकुल) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह सिडकुल की अनुमोदित परियोजना हो और सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त की गयी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए राजस्व विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7. प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस0एल0पी0)/सी संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011/SLC/ No 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. हस्तान्तरित भूमि के उक्तानुसार आंकलित मूल्य के सापेक्ष 100 करोड़ की धनराशि प्रारम्भ में तथा शेष धनराशि 58.25 करोड़ समय-समय पर विक्रय की जानी वाली भूमि से प्राप्त होने पर पांच वर्षों के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
10. एकीकृत औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं संस्थागत प्रयोजन हेतु भूमि में निर्माण हेतु उनसे संबंधित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
12. औद्योगिक आस्थान हेतु हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रक्बा है0
1.	खुरपिया	2, 7मि0 8, 9क,10,11,12,16,17, 18क, 18ग ,20, 21 मि0,25,74,75,76क,77क,78,79,80,81,82,83,84,85,86, 87, 88, 89, 90,91,92,93,94 ख,96 मि0,97मि0,	130.1086
2.	बण्डिया	5/1,5/7,8/1, 8/2मि., 8/4मि.,8/5मि. 8/6, 8/7मि., 16/1, 16/3, 5/3,6/1, 7/1	21.5284
3.	देवरिया	102	14.1050
4.	गौरीकला	97,105,106,118मि, 119मि,125, 127, 130, 131,132, 133, 134, 135, 136, 137मि.,139,140, 141, 145 मि. ,147, 149, 151, 154, 156, 157, 158	119.0800
5.	भूड़ागौरी	25, 85, 86क, 87, 92ख, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 117, 118, 126, 58/133	120.9080
			कुल 405.7300 (1002.15 एकड़)

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को समय-समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव।

पृ०सं०- 667 / XVIII (II) 2016-18(121) / 2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
5. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल देहरादून।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०पी०जोशी)
अपर सचिव।